RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 18 DECEMBER TO 24 DECEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 17 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी काउंसिल की बैठक लॉटरी के लिए सिंगल रेट पर विचार

Page 3

वाहन उद्योग पर वित्तमंत्री का बयान अफसोस जनक

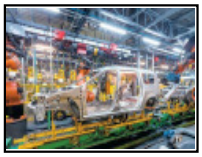

Page 4

अब इलेक्ट्रिक कार लेने में नहीं होगी हिचक!

Page 7

editoria!

समझौते के संकेत

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते की एकतरफा खबर से दुनिया ने राहत की सांस ली है। शेयर बाजारों ने इसका उछाल के साथ स्वागत किया और न सिर्फ अमेरिकी बल्कि भारत समेत कई एशियाई बाजारों में भी इस खबर से तेजी देखी जा रही है। चीन की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो बाजार के उत्साह को देखते हुए थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, केवल इसे आधिकारिक रूप देना बाकी है। अमेरिकी सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच पहले चरण की ट्रेड डील पर सहमति गुरुवार को ही बन गई थी। इसके तहत 160 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर 15 दिसंबर से प्रस्तावित अमेरिकी आयात शुल्क टल जाएगा। जिन उत्पादों पर यह लगना था उनमें जूते, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने भी शामिल थे। चीन से आने वाले सामान पर पहले से लग रहे आयात शुल्क को भी घटाकर आधे पर ला दिया जाएगा। चीन अगले साल अमेरिका से 50 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुएं खरीदने पर सहमत हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच वार्ता का यह दौर अक्टूबर से ही जारी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि इस वर्ष के अंत तक पहले चरण की डील हो सकती है। हालांकि, बीच-बीच में ट्रंप कुछ विरोधाभासी बयान भी दे देते थे जिससे आशंकाएं बढ़ जाती थीं। गनीमत है कि ट्रंप ने हालात की गंभीरता को समझा है। इधर कुछ समय से विश्व अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन के जो लक्षण देखे जा रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर को माना जा रहा है, जिसका दोष सीधे-सीधे ट्रंप पर जाता है। आईएमएफ का अनुमान है कि आयात कर को हथियार बनाकर लड़ी जा रही इस लड़ाई के चलते अमेरिका की ग्रोथ में 0.6 प्रतिशत और चीन की ग्रोथ में 2 प्रतिशत की कमी आई है। ट्रेड वॉर के चलते चीन ने अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदना बंद कर दिया था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में अमेरिकी फार्म एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से घटकर 7 अरब डॉलर रह गया है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों के मुताबिक चीनी सामानों के इंपोर्ट पर अमेरिकी कंपनियां अपनी सरकार को हर महीने 5 अरब डॉलर का आयात शुल्क चुका रही हैं। आयात शुल्क में 50 प्रतिशत कमी से इन कंपनियों को हर महीने 2.5 अरब डॉलर की बचत होगी। बहरहाल, दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर खत्म होना भारत के लिए भी पॉजिटिव होगा। अनिश्चितता खत्म होने से निवेशकों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रुझान तभी देखने में आएगा जब टकराव पूरी तरह समाप्त हो जाए। अभी तो यह आशंका ही बरकरार है कि गतिरोध टूटा भी है या नहीं।

खाने-पीने का सामान महंगा होने से 0.58% बढ़ी थोक महंगाई

नई दिल्ली। खाने-पीने के सामान के दाम में तेज उछाल आने से होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 0.58% पर पहुंच गई। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से सोमवार को जारी डेटा के मुताबिक WPI बेस्ड इन्फ्लेशन अक्टूबर में 0.16ङ्ग थी। रेटिंग कंपनी ध्ँ की प्रिंसिपल इकनॉमिस्ट अदिति नायर कहती हैं, 'प्राइमरी फूड आर्टिकल्स के दाम में उम्मीद के मुताबिक 11.1% की तेज उछाल आई जो 71 महीने में सबसे ज्यादा थी। इसके चलते ङ्ग्ध्ब बेस्ड इन्फ्लेशन बढ़ी और पिछले दो महीने से इसमें चल रही गिरावट का रुझान नवंबर 2019 में पलट गया।' नवंबर में प्याज का दाम 172.3% उछला, सब्जियों की कीमत में 45.32% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन आलू का दाम पिछले महीने के मुकाबले 8.51% कम रहा। WPI में 64.23% वेट रखने वाले मैन्युफैक्चर्ड प्रॉडक्ट्स में महंगाई की दर -0.84% पर जस की तस रही, लेकिन फ्यूल और पावर की महंगाई दर -7.32% रही। पिछले हफ्ते जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों, दालों और प्रोटीन से भरपूर आइटम्स का दाम बढ़ने से रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर में तीन साल के पीक 5.54% पर पहुंच गई थी।

अदिति के मुताबिक, अगली तिमाही में जब सब्जियों के दाम सामान्य स्तर पर आ जाएंगे तो प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन में तेज गिरावट आएगी, लेकिन उससे पहले दिसंबर में इसमें उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। कोर इन्फ्लेशन यानी नॉन-फूड मैन्युफैक्चर्ड प्रॉडक्ट्स में महंगाई नवंबर में लगातार चौथे महीने घटकर 1.9% हो गई, जिससे इकनॉमी में डिमांड कमजोर रहने की पुष्टि होती है। इकरा का अनुमान है कि औसत WPI इन्फ्लेशन FY 20 में 1.5% हो सकती है जबकि केयर रेटिंग्स ने साल के बाकी समय में इसके 1% से नीचे बने रहने का अनुमान दिया है।

केयर रेटिंग्स के चीफ इकनॉमिस्ट मदन सबनवीस के मुताबिक, 'जनवरी के बाद खाने-पीने के सामान के दाम में कमी आ सकती है। तब WPI में कमी आएगी।' दिसंबर में महंगाई बढ़ने के आसार पर इकनॉमिस्ट्स अगले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेट कट नहीं होने का अनुमान लगा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल कई बार में रेपो रेट में कुल 135 बेसिस प्वाइंट यानी 1.35 पर्सेंटेज प्वाइंट की कमी की है। इंडिया रेटिंग्स के प्रिंसिपल इकनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं, 'RBI यहां तक कि फरवरी 2020 के पॉलिसी रिव्यू में भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा।'

दरअसल, मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में फिस्कल डेफिसिट GDP के 3.3% के बराबर रहने का अनुमान दिया गया था, लेकिन इसके उससे ज्यादा होने के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से पॉलिसी रेट में की गई कटौती का असर रियल इकनॉमी में नहीं दिख रहा है, जबकि ग्रोथ रेट में आई गिरावट को देखते हुए RBI की तरफ से पॉलिसी रेट में और कटौती किए जाने की दरकार है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पांच दिसंबर के पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट को जस का तस रखा था और जीडीपी फोरकास्ट 6.1% से घटाकर 5% कर दिया था।

मझगांव डॉक को आईपीओ लाने की शेयर बाजार से मिली मंजूरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। शेयर बाजार को दी गई ताजा सूचना के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने आईपीओ पेश करने के लिए मंजुरी लाने के लिए अगस्त में सेबी के समक्ष मसौदा दस्तावेज जमा किया था और उसे 13 दिसंबर को 'टिप्पणी' प्राप्त हुई है। किसी भी कंपनी को आईपीओ, एफपीओ और राइट इश्यू लाने के लिए सेबी की ओर से सकारात्मक टिप्पणी की जरूरत होती है। दस्तावेज के मसौदे के मुताबिक सरकार इसके माध्यम से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स में अपने 2.8 करोड़ शेयर बेचेगी। मझगांव देश में समुद्री जहाज बनाने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है। यह देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करती है। कंपनी को इससे पहले सेबी ने अगस्त 2018 में भी आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी दे दी थी पर कंपनी उस समय बाजार में शेयर नहीं ला सकी थी। श सरकार ने चालू वित्त वर्ष में चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेच कर 1.05 लाख करोड रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 का शुभारंभ 20 को

संभागायुक्त त्रिपाठी होगें मुख्य आतिथी, मनु करेंगे अध्यक्षता

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रदेश के औद्योगिक विकास व यहां के उद्यमियों को नवीनतम तकनीकी प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए आयोजित इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ 20 दिसंबर को किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी होगें। वहीं अध्यक्षता सहारा समय के ग्रुप एडिटर श्री मनोज मनु करेंगे।

इंडियन प्लास्टपेक फोरम , एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश, फ्युचर कम्युनिकेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह प्रदर्शनी 20 से 23 दिसंबर तक लाभगंगा एक्झीबिशन सेन्टर इंदौर चलेगी। इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 का विधिवत शुभारंभ 20 दिसंबर को दोपहर 1 बजे इंदौर संभाग कमिश्नर श्री आकाश त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य एवं सहारा समय के ग्रुप एडिटर श्री मनोज मनु की अध्यक्षता में होने जा रहा है। इस आयोजन में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, सचिव सुनील व्यास, इंडियन प्लास्टपेक फोरम में अध्यक्ष सचिन बंसल, फ्युचर कम्यूनिकेशन के अमेय गोखले, लक्ष्मण दुबे सहित, उद्योगपति, एग्जिबिटर्स एवं गणमान्यजन आदि उपस्थित होगे।

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया एवं मानद सचिव श्री सुनील व्यास ने बताया कि यह इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुडे मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयां, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स आदि के लिए लाभदायक होगा जहां इंदौर सहित एक्सपों में सम्मिलित होने वाले उद्योगपति और निर्माता उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियों से संवाद कर सकेगें। इस आयोजन में इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कम्पोनेंट,ऑटोमेशन एंड रोबोटिक आदि उत्पादों एवं मशीनरी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें देशी एवं विदेशी कंपनियों के उत्पादों का प्रदर्शन होगा। इस चार दिवसीय प्रदर्शनी में 300 से अधिक स्टॉल्स लगाये जा रहे है। प्रदर्शनी को विजिटर्स के लिए निःशुल्क रखा गया है। उद्योगपतिगण, उद्यमी युवावर्ग एवं व्यवसाय क्षेत्र से जुडे व्यक्ति इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर नई तकनीकी की जानकारी लेकर अपने उद्योग व्यवसाय में इसे अपनाकर लाभ ले सकेगें।

IMF दे सकता है झटका

गीता गोपीनाथ ने कहा-घटा सकता है आर्थिक विकास दर अनुमान

मुंबई। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने मंगलवार को कहा कि आईएमएफ जनवरी में भारत की वृद्धि के अपने अनुमान में उल्लेखनीय कमी कर सकता है। इससे पहले कई अन्य एजेंसियां भारत के विकास दर अनुमान में कटौती कर चुके हैं। भारत में जन्मी गोपीनाथ ने यहां टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित इंडिया इकनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि संस्थान ने इससे पहले अक्टूबर में अनुमान जारी किया था और जनवरी में इसकी समीक्षा करेगा।

साढ़े 6 साल के निचले स्तर पर ग्रोथ

भारत में उपभोक्ता मांग और निजी क्षेत्र के निवेश में आई कमी तथा कमजोर पड़ता निर्यात कारोबार जीडीपी वृद्धि में आई सुस्ती के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में छह साल के निम्न स्तर 4.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक और अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले कई अन्य विश्लेषकों ने 2019-20 के लिए वृद्धि के अपने अनुमान की समीक्षा करते हुए इसे कम किया है।

जनवरी में नए आंकड़े जारी करेगा आईएमएफ

गोपीनाथ ने कहा कि भारत ही एकमात्र उभरता हुआ बाजार है, जो इस तरह आश्चर्यचकित कर सकता है। उन्होंने कहा, 'यदि आप हाल के आने वाले आंकड़ों पर गौर करेंगे, हम अपने आंकड़ों को संशोधित करेंगे और जनवरी में नए आंकड़े जारी करेंगे। इसमें भारत के मामले में उल्लेखनीय रूप से कमी आ सकती है।' हालांकि, उन्होंने कोई आंकड़ा बताने से इनकार कर दिया, यहां तक यह भी नहीं बताया कि क्या यह पांच प्रतिशत से कम रह सकता है।

2019 में विकास दर 6.1 फीसदी रहने का है अनुमान

आईएमएफ ने अक्टूबर में भारत की 2019 की आर्थिक वृद्धि की दर को 6.1 प्रतिशत और 2020 में इसके सात प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया। गोपीनाथ ने वर्ष 2025 तक भारत के 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लेकर भी संशय जताया। इसके समर्थन में उन्होंने अपनी गणना भी प्रस्तुत की। 38 वर्षीय गोपीनाथ ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को पिछले छह साल के छह प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले बाजार मूल्य पर 10.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि हासिल करनी होगी। स्थिर मूल्य के लिहाज से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करनी होगी।

भूमि और श्रम बाजार में सुधार करना जरूरी

गोपीनाथ ने कहा कि यदि सरकार को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करना है तो उसे अपने मजबूत बहुमत का इस्तेमाल भूमि और श्रम बाजार में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को ऊंची आकांक्षा रखना अच्छा है और भारत इस दिशा में काफी कुछ कर भी रहा है। उन्होंने भारत की वित्तीय स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए चेताया कि राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत के दायरे से आगे निकल जाएगा। वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर उन्होंने कार्पोरेट कर में कटौती का जिक्र किया, लेकिन कहा कि इसके साथ ही राजस्व बढ़ाने के किसी उपाय की घोषणा नहीं की गई।

'बीएसएनएल को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना से चालू वित्त वर्ष में 1,300 करोड़ रुपये की बचत'

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्त

सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने मंगलवार को कहा कि 78,569 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुना है। इससे कंपनी को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में वेतन मद में 1,300 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है। योजना जनवरी से अमल में आएगी। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने संवाददाताओं से कहा, "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) 31 जनवरी 2020 से प्रभाव में आएगी। हमारा लक्ष्य है कि जिन लोगों ने वीआरएस के लिये आवेदन किया है, उन पर विचार किया जाए और उसे मंजूरी दी जाए।" एमटीएनएल के साथ विलय के बारे में पुरवार ने कहा कि चर्चा शुरू हुई है और दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठक हुई है। उन्होंने कहा, "इस समय हमारा लक्ष्य नेटवर्क एकीकरण और परिचालन में तालमेल पर है। इसको लेकर चर्चा शुरू हुई है।" चूंकि वीआरएस 31 जनवरी 2020 से प्रभाव में आएगी, कंपनी को वेतन मद में चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में 1,300 करोड़ रुपये की बचत होगी। उच्चतम न्यायालय के समायोजित सकल राजस्व पर हाल के फैसले से कंपनी के ऊपर वैध बकाये के बारे में पुरवार ने कहा, "वित्तीय दबाव परिदृश्य को देखते हुए हमने सरकार से बकाये की वसूली पर पुनर्विचार करने या कंपनी को जो राशि देनी है, उसके बराबर समान राशि के बराबर इक्विटी पूंजी डालने को कहा है।"

फिक्की की समिति तस्करी पर नजर रखने के लिये तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दरें यथावत रखने के पक्ष में

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की बैठक से एक दिन पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की की एक इकाई ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दर को मौजूदा स्तर पर ही बनाये रखने का आग्रह किया है। इस निकाय का कहना है कि इन उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ने से तस्करी बढ़ेगी और उसका घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल असर होगा। तंबाकू सहित विभिन्न प्रकार की नकदी फसलें उगाने वाले किसानों से जुड़े संगठन 'दि फेडरेशन आफ आल इंडिया फार्मर एसोसियेशंस (एफएआईएफए) ने भी सरकार से आग्रह किया है उसे इस तरह की कराधान नीति अपनानी चाहिये जिससे कि देश में सिगरेट की तस्करी हतोत्साहित हो।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे एक पत्र में एफएआईएफए ने कहा है कि जब भी वैधानिक रूप से बिकने वाली सिगरेट पर ऊंचा कर लगाया जाता है तब देश में तस्करी, अवैध और निषिद्ध उत्पादों की आवक में वृद्धि देखी गई है। संगठन ने वित्त मंत्री से ऐसे तंबाकू उत्पादक किसानों की रोजी रोटी बचाने का आग्रह किया है। वर्तमान में देश में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 28 प्रतिशत की दर से लगता है जबकि इनमें विभिन्न उत्पादों पर उपकर की दर 61 से 204 प्रतिशत के दायरे में लगाई गई है। फिक्की की तस्करी और नकली उत्पाद गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को पहुंच रहे नुकसान के खिलाफ गठित समिति (कास्केड) ने कहा है कि इस साल विभिन्न एजेंसियों ने 18 करोड़ रुपये मूल्य की तस्करी की सिगरेट जब्त की है। समिति ने कहा है कि तंबाकू पर कर में की गई वृद्धि की वजह से पिछले कुछ सालों के दौरान इन उत्पादों की तस्करी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2005 से 2018 के बीच अवैध सिगरेट का व्यापार 12.5 अरब सिगरेट से बढ़कर 26.5 अरब सिगरेट पर पहुंच गया। फिक्की कास्केड के सलाहकार और अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पी.सी. झा ने कहा, "हमें इस बात को याद रखना होगा कि कर की ऊंची दर से कर अपवंचना को ही प्रोत्साहन मिलता है।" उन्होंने कहा, "इसलिये यह जरूरी है कि लोगों को वैध उत्पाद उचित दाम पर उपलब्ध हों और यह हमारे हित में होगा कि हम इस मामले में गंभीरता के साथ ध्यान देते हुये कर सिगरेट पर कर ढांचे को तर्कसंगत रखें। ऐसा कर हम असामाजिक तत्वों को देश में गहरी पैठ बनाने से रोक सकेंगे।" एफएआईएफए से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में नकदी फसलें उगाने वाले किसान जुड़े हैं। संगठन का कहना है कि तंबाकू उत्पादों पर उतना ही कर लगाया जाना चाहिये जिससे कि तस्करी का बढ़ावा नहीं मिले और देश में वैध उत्पादों की बिक्री वहनीय बनी रहे।

5 लाख रुपये तक की इनकम हो टैक्स फ्री, FICCI ने सरकार को दिया सुझाव

नई दिल्ली। उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से आगामी बजट में गुड्स एंड सर्विसेज की मांग बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में राहत देने का आग्रह किया है। फिक्की ने कहा कि सरकार को एक्सपोर्ट को फिर से सक्रिय करने, रोजगार को प्रोत्साहित करते और देश में बिजनेस करने की लागत को कम करने के उपायों की घोषणा करनी चाहिए। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट (Budget 2020) पेश करेंगी।

20 लाख रुपये की इनकम पर लगे 30% टैक्स

उद्योग संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार को सालाना 20 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स से 30 फीसदी के हाईएस्ट रेट से इनकम टैक्स वसूलना चाहिए. मौजूदा इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, 10 लाख रुपये ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिक्की का कहना है कि भारत के मुकाबले अन्य देशों में हाइएस्ट टैक्स रेट के लिए इनकम की सीमा अधिक है। भारत में इनकम टैक्स हाईएस्ट टैक्स रेट के लिए इनकम सीमा बढ़ाने की जरूरत है।

5 लाख रुपये तक की इनकम हो टैक्स फ्री

प्री-बजट 2020-21 (Pre-Budget 2020-21) उम्मीदों में फिक्की ने सुझाव दिया कि इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स स्लैब में भी बदलाव होना चाहिए. फिक्की का कहना है कि केंद्र सरकार को 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। 5 से 10 लाख सालाना आमदनी पर 10 फीसदी और 10 से 20 लाख रुपये सालाना आय पर 20 फीसदी और 20 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स वसूलना चाहिए.

मौजूदा टैक्स स्लैब

फिलहाल, इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है. 2.5 लाख से 5 लाख की सालाना आमदनी पर 5 फीसदी की दर इनकम टैक्स लगता है। वहीं, 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना पर इकनम टैक्स रेट 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से कर देना पड़ता है।

रिबेट के कारण 5 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगता टैक्स

फिक्की के मुताबिक, बजट 2019 में मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ. हालांकि फाइनेंस (No.1) एक्ट, 2019 के तहत टैक्स रिबेट की लिमिट बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई। इससे 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता।

जीएसटी काउंसिल की बैठक

लॉटरी के लिए सिंगल रेट पर विचार

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक होने वाली है। ऐसी चर्चा है कि सरकार जीएसटी रेट बढ़ा सकती है। इसके अलावा आज लॉन्ग टर्म लीज को उएऊ से बाहर करने और कुछ कैटेगरीज पर रेट 2% बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा सरकार लॉटरी के लिए भी जीएसटी रेट में बदलाव कर सकती है। 50000 करोड़ रुपये की इस इंडस्ट्री को दो अलग-अलग दरों से समस्या हो रही है। अभी लॉटरी पर 12% और 28% जीएसटी लगता है।

जीएसटी कलेक्शन में लक्ष्य से काफी पीछे

ऐसी चर्चा है कि सरकार जीएसटी रेट बढ़ा सकती है। दरअसल इस वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन के मामले में सरकार लक्ष्य से 40 फीसदी पीछे चल रही है। जानकारी के मुताबिक, उएऊ काउंसिल इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। इससे इंडिया इंक के लिए कैश फ्लो की मुश्किल हो सकती है। इसे 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने पर विचार किया जा रहा है।

एक्सपोर्ट रिफंड के लिए सिंगल विंडो पर विचार

इसके अलावा सरकार सभी एक्सपोर्टर रिफंड्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पर भी विचार कर रही है। अभी एक्सपोर्टर्स को रिफंड के लिए दो अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है।

कंपनियों के कैश फ्लो पर हो सकता है असर

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'यह माना जा रहा है कि अगर सप्लायर इनवॉयस अपलोड करने में असफल रहता है तो क्रेडिट पर बंदिश लगानी चाहिए।' अभी एक एंटिटी को योग्य रकम के 20 पर्सेंट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है। इसे घटाकर 10 पर्सेंट करने या फ्रॉड के मामले में इसकी अनुमति नहीं देने का प्रपोजल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से कंपनियों का कैश फ्लो घट सकता है। किसी एंटिटी के सप्लायर की ओर से किए गए भुगतान को लेकर संबंधित इनवॉयस अपलोड न करने पर उस एंटिटी के लिए पात्र रकम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को सरकार ने अक्टूबर में सीमित कर 20 पर्सेंट कर दिया था।

सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था क्लेम

इससे पहले ऐसी कोई बंदिश नहीं थी और फर्में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करती थी। जाली इनवॉयस से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद ये बंदिशें लगाई गई थीं। रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने के लिए बनाई गई अधिकारियों की कमेटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इस तरह के कदम का पक्ष लिया है।

आमदनी बढ़ाने पर सरकार की नजर

उएऊ काउंसिल की बुधवार को होने वाली मीटिंग में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ उपायों पर विचार किया जा सकता है। आमदनी बढ़ाने के साथ ही टैक्स चोरी को रोकने के लिए उएऊ कानून के विशेष प्रावधान में बदलाव पर विचार विमर्श होने की संभावना है। उएऊ काउंसिल सेक्रटरिएट ने राज्यों को उएऊ में बदलाव पर सुझाव देने के लिए कहा है। राज्य टैक्स रेट को संतुलित बनाने के साथ ही छूट को कम करने जैसे मुद्दों पर सुझाव देंगे। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एम एस मणि ने कहा, 'इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बंदिश लगने से कैश फ्लो पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।'

अप्रैल 2020 से पहले लागू नहीं करे सरकार- प्रतीक जैन

ईएफ के लीडर (इनडायरेक्ट टैक्सेज) प्रतीक जैन ने बताया, '20 पर्सेंट का रेट हाल ही में लागू किया गया है और कंपनियां अभी इसके मुताबिक खुद को ढाल रही हैं। कोई अन्य बदलाव होने से समस्या बढ़ जाएगी।' जैन ने कहा कि सरकार को इसे 1 अप्रैल, 2020 से घटाने पर विचार करना चाहिए, जब नया रिटर्न फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद दो-तीन महीने तक इसे केवल वेंडर तक ही सीमित रखना चाहिए। इससे इंडस्ट्री को नए नियमों को समझने के लिए कुछ समय मिल सकेगा।

रियल एस्टेट को राहत की उम्मीद

आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने वाले उपाय, लॉटरी पर इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स में बदलाव और निर्यातकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया आसन करने की व्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि सरकार रेवेन्यू कलेक्शन तो बढ़ाना ही चाहती है, लेकिन इसके साथ कुछ उद्योगों को हो रही समस्याओं को भी दूर करना चाहती है। दो लोगों ने बताया कि सरकार कुछ वस्तुओं पर 2 प्रतिशत का 'अस्थायी सेस' लगाने पर विचार कर रही है। ये वस्तुएं खासतौर पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी वाली कैटेगरी में हैं।

30 साल से ज्यादा की लीज उएऊ के दायरे से बाहर हो सकती है

जीएसटी काउंसिल लॉन्ग टर्म लीज पर लगने वाले रेट्स की पिक्चर भी स्पष्ट कर सकती है जिनसे मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टरों की कई कंपनियों को फायदा होगा। 30 साल या इससे ज्यादा की लॉन्ग टर्म लीज को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की योजना है, बशर्ते ये राज्य सरकारों की ओर से दी गई हों या उन इकाइयों की ओर से जिनमें केंद्र सरकार की कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

लॉन्ग टर्म लीज पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग

कई कंपनियों ने लॉन्ग टर्म लीज ट्रांजैक्शंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी के खिलाफ अदालतों में मुकदमे किए हैं। जीएसटी एजेंडा के नोट में कहा गया है कि अगर भूखंड पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का स्वामित्व हो तो उसके लॉन्ग टर्म लीज पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए लॉन्ग टर्म लैंड लीज को जीएसटी से बाहर करना उन उपायों का हिस्सा हो सकता है, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग में नया निवेश लाने में मदद मिल सकती है।

अडिशनल सरचार्ज पर विचार

सूत्रों ने बताया कि सरकार मौजूदा जीएसटी स्लैब्स पर अडिशनल सरचार्ज लगाने पर विचार कर सकती है ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़े। साथ ही, वह एसजीएसटी और सीजीएसटी के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे पर भी गौर कर सकती है। हालांकि एजेंडा डॉक्युमेंट में इसका जिक्र नहीं है।

कृषि विशेषज्ञों ने कृषि कच्चे माल पर जीएसटी समाप्त करने फसल बीमा योजना में सुधार करने की मांग की

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने मंगलवार को सरकार से कृषि कच्चे माल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को हटाने, फसल बीमा योजना में सुधार लाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय पट्टे पर ली गई भूमि के किराये को शामिल करने तथा कृषि-जिंसों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने जैसे सुझाव दिये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस बैठक के दौरान, जैविक खेती को बढ़ावा देने के उपायों, भ्रूण, पशु और वीर्य पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) में सुधार करने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पुनः समीक्षा करने जैसी कुछ अन्य सिफारिशें भी की गईं। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के दिनेश कुलकर्णी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ''खाद, बीज और कृषि उपकरण जैसे हर कृषि कच्चे माल पर जीएसटी शून्य होना चाहिए।'' उन्होंने यह भी कहा कि कृषि-जिंसों का वायदा कारोबार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उपभोक्ताओं या किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विभिन्न फसलों की खरीद बढ़ाने का भी अनुरोध किया। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने मांग की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को नई फसल बीमा और क्षतिपूर्ति योजना से बदल देना चाहिये या किसान आपदा और राहत राहत आयोग का गठन किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को प्रसंस्कृत खाद्य और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करना चाहिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक अरुण रस्ते ने कहा, ''हम चाहते हैं कि भ्रूण, पशु और वीर्य पर आयात शुल्क को शून्य किया जाए। सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी- छ) के कार्यान्वयन की गति को भी तेज करनी चाहिए और इसके लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए।''

एनडीपी- दो, का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना है, जिसपर एक अरब डॉलर की लागत आने का अनुमान है। इसमें से 50 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा वहन किया जाएगा और 30 प्रतिशत केंद्र और शेष 20 प्रतिशत एनडीडीबी द्वारा खर्च किया जाएगा। कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन (सीआईएफए) के महासचिव बी डी रामी रेड्डी ने कहा कि सरकार को फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करते समय लीज पर लिए खेत के किराये पर भी गौर करना चाहिये जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त, कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन मंत्रालय के साथ-साथ नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल थे।

वाहन उद्योग पर वित्तमंत्री का बयान अफसोस जनक

नई दिल्ली। एजेंसी

हाल ही में जब सुश्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अघोषित आँकड़ों का उल्लेख किया, जैसे कार की बिक्री में गिरावट के कारण सहस्राब्दियों से कारों की खरीद नहीं हो रही है, लॉजिस्टिक व्यवसाय ने ट्रक व्यवसाय को सरल और आसान बना दिया है, ँ्ण कंपनियां लीज़ मॉडल में बदलाव के कारण सिकुड़ रही हैं, आदि। उद्योग और मीडिया ने सीतारमण के व्यापार और उद्योग के ज्ञान की कमी के लिए उनका उपहास किया। यहां तक कि आनंद महिंद्रा जैसे इंडस्ट्री कैप्टन भी उनकी बातों का मजाक उड़ाने के लिए पलट गए। लेकिन बहुत कम मीडिया और निश्चित रूप से उद्योग ने भी महसूस किया है कि भारतीय व्यवसायों के पास अपने व्यापार मॉडल की गहरी परीक्षा थी। जर्मन फर्म द्वारा एक वैश्विक सर्वेक्षण और शोध जो भारत को विस्तृत रूप से कवर करता है, ने वैश्विक मंदी के कारण आसन्न वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए बीस प्रमुख जोखिमों का संकेत दिया है और विशेष रूप से यह मध्यम और दीर्घकालिक में भारत को कैसे प्रभावित करेगा। सर्वेक्षण सह अनुसंधान स्पष्ट है कि जब तक भारतीय व्यवसाय अपने ूंे और व्यापार मॉडल को नहीं बदलते हैं, तो नष्ट हो जाएंगे। इसे इस तरह से समझा जा सकता है।

1.अधिकांश लोग एक-डेढ़ दशक में कारों की खरीद बंद कर देंगे ।
2.लोग परिसंपत्तियों के किराये में वृद्धि करेंगे (इन्हें खरीदने पर) क्योंकि वे कभी भी सुनिश्चित नहीं होंगे कि वे कुछ वर्षों से कहां रह रहे हैं।
3.आवागमन की लागत 'अगला टेलीकॉम बन जाएगी।
4.अधिकांश कारों को पुनर्नवीनीकरण स्टील से बनाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप, अयस्क कंपनियां पेट-ऊपर जाएंगी।
5. स्टील सेक्टर का बड़ा कर्ज बैंकों को वापस नहीं किया जा सकेगा।
6. इलेक्ट्रिक कार, सामान्य पेट्रोल चालित किस्म के लिए 10,000-12,000 की तुलना में लगभग 18 चलती भागों के साथ, ऑटोमोबाइल घटकों उद्योग की मृत्यु को गति देगा।
7.ऑटो कंपोनेंट उद्योग का निधन वैश्विक मिश्र धातु इस्पात क्षेत्र (अयस्क और फेरोलोइल सहित) को प्रभावित करेगा।
8. यदि तेल की खपत में गिरावट आई है तो तेल के किन्नर अपने कर्ज को नहीं चुका पाएंगे।
9.इलेक्ट्रिक वाहन एक असीमित वारंटी के साथ आएंगे। ङ इसका मतलब है कि एक बार वाहन खरीदने के बाद, आपको कभी भी दूसरा खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं (सऊदी अरब, ईरान, इराक, रूस, नाइजीरिया आदि) संकट में चली जाएंगी।
11. इन तेल उत्पादक देशों से आने वाली कुछ धनराशि गायब हो जाएंगे और दुनिया एक अधिक शांतिपूर्ण जगह बन जाएगी।
12. नकद-समृद्ध ऑटोमोटिव स्नेहक कंपनियों को पता चलेगा कि वास्तव में लुब्रिकेट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
13. 3ॐ प्रिंटिंग विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच वेतन मध्यस्थता को भी समाप्त कर देगी।
14. रोबोटिसेशन (या कृत्रिम बुद्धिमत्ता) नौकरियों को साफ कर देगा (जैसा कि बैंकिंग क्षेत्र में है, जहां व्यवसाय भर्ती की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा है)
15. कई तरह के कौशल अप्रचलित हो जाएंगे (उदाहरण के लिए माइक्रोसर्जिकल), क्योंकि एक रोबोट इसे बेहतर करेगा।
16. अक्षय ऊर्जा दीर्घकालिक कोयला गिरावट को शुरू करेगी।
17. हजारों लोगों को रोजगार देने वाले बड़े कोयले के गढ़ दिवालिया (पहले से हो रहे) के लिए दायर करेंगे।
18. बैंक एक जगह के बजाय एक अवधारणा बन जाएंगे, बैंक लोगों की तुलना में सिस्टम के बारे में अधिक हो जाएंगे।
19. दुनिया धन की बहुतायत और अपेक्षाकृत सीमित खर्च से उत्पन्न होने वाले अपस्फीति की ओर बढ़ेगी।
20. नई सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष (औसत) हो जाएगी।

स्त्री-पुरुष असमानता में भारत 112वें स्थान पर, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी में स्थिति ज्यादा खराब

नयी दिल्ली। एजेसी

महिलाओं की स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और आर्थिक भागीदारी क्षेत्र में स्थिति खराब होने के बीच स्त्री - पुरुष असमानता पर तैयार रिपोर्ट में भारत एक साल पहले के मुकाबले चार पायदान फिसलकर 112 वें स्थान पर पहुंच गया। स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी इन दो क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत सबसे नीचे स्थान पाने वाले पांच देशों में शामिल है। विश्व आर्थिक मंच की महिला और पुरुषों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते फासले से संबंधित इस वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भारत पिछले साल इस सूची में 108 वें पायदान पर था। विश्व आर्थिक मंच की स्त्री - पुरुष अंतर रिपोर्ट में भारत का स्थान चीन (106), श्रीलंका (102), नेपाल (101), ब्राजील (92), इंडोनेशिया (85) और बांग्लादेश (50) से भी नीचे है। स्त्री - पुरुष के बीच सबसे ज्यादा समानता आइसलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री - पुरुष असमानता को चार मुख्य कारकों के आधार पर तय किया गया है। इनमें महिलाओं को उपलब्ध आर्थिक अवसर , राजनीतिक सशक्तिकरण , शैक्षणिक उपलब्धियां तथा स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा शामिल है। स्त्री - पुरुष के बीच अंतर सूचकांक में यमन की स्थिति सबसे खराब है। उसे 153 वां स्थान मिला है जबकि इराक को 152 वें और पाकिस्तान को 151 वें पायदान पर रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच ने कहा , '2019 में स्त्री - पुरुष के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतर है उसे पाटने में 99.5 साल लगेंगे। वहीं 2018 के मुकाबले इसमें सुधार देखा गया है। इस समय अनुमान लगाया था कि महिला पुरुषों के बीच असमानता को दूर करने में 108 साल लगेंगे। ' इस प्रकार , राजनीतिक असमानता को खत्म करने में पिछले वर्ष 107 साल के मुकाबले अब 95 साल लगेंगे। हालांकि , आर्थिक अवसर के मामले में स्थिति खराब हुई है। आर्थिक अवसरों के मामले में स्त्री - पुरुष के बीच व्याप्त अंत को कम करने में 257 साल लगेंगे। पिछले साल इसमें 202 साल लगने का अनुमान जताया गया था। विश्व बैंक ने अपनी पहली स्त्री - पुरुष अंतर रिपोर्ट 2006 में पेश की थी। उस समय भारत 98 वें पायदान पर था। आज भारत की रैंकिंग उससे भी कम है। तब से लेकर , रैंकिंग के लिए उपयोग होने वाले चार में से तीन कारकों में भारत की स्थिति खराब हुई है। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की रैंकिंग सुधरी है जबकि स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में वह फिसलकर 150 वें स्थान , आर्थिक भागीदारी एवं अवसर के मामले में 149 वें पायदान और शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में 112 वें पायदान पर आ गया है। मंच ने कहा कि भारत (35.4 प्रतिशत), पाकिस्तान (32.7 प्रतिशत), यमन (27.3 प्रतिशत), सीरिया (24.9 प्रतिशत) और इराक (22.7 प्रतिशत) में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बेहद सीमित हैं। उसने कहा कि भारत उन देशों में है , जहां कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (13.8) बहुत कम है। विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के मामले में चार बड़े देशों भारत , वियतनाम, पाकिस्तान और चीन की स्थिति बहुत खराब है। यहां लाखों महिलाओं की पुरुष के समान स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। मंच ने भारत में (100 लड़कों पर सिर्फ 91 लड़कियां) और पाकिस्तान (100 लड़कों पर 92 लड़कियों) जैसे कम लिंग अनुपात को लेकर भी चिंता जताई है। मंच ने कहा कि भारत ने अपनी समग्र असमानता को दो - तिहाई तक किया है लेकिन भारतीय समाज के एक बड़े छोर में महिलाओं की स्थिति अनिश्चित है और आर्थिक असमानता विशेष रूप से गहरी होती जा रही है। साल 2006 के बाद से स्थिति खराब हुई है और भारत सूची में शामिल 153 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जहां , स्त्री - पुरुष के बीच आर्थिक असमानता , उनके बीच की राजनीतिक असमानता से भी बड़ी है। लैंगिक समानता के मामले में नॉर्डिक देशों की स्थिति शीर्ष पर बनी हुई है। आइसलैंड के बाद शीर्ष चार में नॉर्वे , फिनलैंड और स्वीडन का स्थान है। शीर्ष दस देशों में इनके अलावा , निकारागुआ , न्यूजीलैंड , आयरलैंड , स्पेन , रवांडा और जर्मनी हैं।

सरकार का 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड देने का वादा, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड तक पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया है। सरकार ने मंगलवार को महत्वाकांक्षीय राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में संबद्ध पक्ष आगामी वर्षों में सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इस मिशन के तहत देशभर, विशेषरूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त आप्टिकल फाइबर केबल मार्ग बिछाया जाएगा। साथ ही 2024 तक टावर का घनत्व भी 0.42 से बढ़ाकर एक टावर प्रति हजार आबादी किया जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को इस मिशन का शुभारंभ किया। इसके तहत मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का भी लक्ष्य है। प्रसाद ने कहा, ''2022 तक हम देश के सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचा देंगे। देश में टावरों की संख्या बढ़कर 10 लाख हो जाएगी, जो अभी 5.65 लाख है।'' उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत टावरों का 'फाइबराइजेशन' बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो जाएगा, जो अभी 30 प्रतिशत है। प्रसाद ने कहा कि इस मिशन के जरिये शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा। प्रसाद ने वादा किया, ''हम चरणबद्ध तरीके से गति को भी बढ़ाकर 50 एमबीपीएस तक पहुंचाएंगे।'' उन्होंने राज्यों से इस मिशन में पूरा सहयोग देने को कहा जिससे प्रौद्योगिकी के लाभ को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस मिशन के तहत संबद्ध पक्ष आगामी वर्षों में 100 अरब डॉलर या सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इसमें 70,000 करोड़ रुपये यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्त आयोग ने सीतारमण को दी 2020-21 की रिपोर्ट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी । एन.के.सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी थी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ''15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के.सिंह ने आयोग के अन्य सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्तमंत्री से मुलाकात की और उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के लिये आयोग की रिपोर्ट दी।'' 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को किया था। आयोग को एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिये सुझाव देने का काम दिया गया था। राष्ट्रपति की अधिसूचना में आयोग के संबंध में विस्तृत संदर्भ सामग्री दी गयी थी।

दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लिए शुल्क जारी रखने का निर्णय स्वागतयोग्य: सीओएआई

नई दिल्ली। मोबाइल सेवा कंपनियों के मंच सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने घरेलू नेटवर्क पर एक सेवा प्रदाता के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर फोन करने के लिए कॉल टर्मिनेशन शुल्क जारी करने के दूरसंचार नियामक ट्राई के निर्णय का स्वागत किया है। सीओएआई का मानना है कि इससे वित्तीय संकट से गुजर रहे इस क्षेत्र के लिए मदद मिलेगी। सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने ट्राई के निर्णय पर एक बयान में कहा, 'यह सही दिशा में और स्वागतयोग्य कदम है। सीओएआई का हमेशा यह कहना रहा है कि भारत में कॉल करने वाले पक्ष पर भुगतान के उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था हमने लागू की हुई है, उसमें लागत आधारित आईयूसी दूसरे नेटवर्क की कॉल को जोड़ने का खर्च हमेशा लगाया ही जाना चाहिए। यह व्यवस्था पूरी दुनिया में है।' मैथ्यूज ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र इस समय वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ''हम इस संकट के समाधान में सरकार और नियामक की ओर से बराबर मदद जारी रखे जाने की उम्मीद रखते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मंगलवार को किसी आपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया। अब यह शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा। इन शुल्कों को अब एक जनवरी, 2021 से समाप्त करने का प्रस्ताव है।

कंपनी कर में कटौती का प्रभाव अगले दो साल में दिखेगा: सीआईआई प्रमुख

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग मंडल सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने मंगलवार को कहा कि संशोधित कंपनी दरें प्रतिस्पर्धी हैं और इसका प्रभाव अगले दो साल में दिखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर दरें कम करने के बारे में उद्योग की हर बात को सुना। किर्लोस्कर ने कहा, ''सितंबर में जब कर दरों में कटौती की घोषणा की गयी, मेरे लिये अचंभित करने वाला था। मुझे वाकई में अच्छा लगा। मुझे लगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी। स्पष्ट रूप से बोलूं तो उन्होंने शब्दशः हमारी बात सुनी।'' बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद उन्होंने पीटीआई भाषा से बातचीत में यह बात कही। बैठक में उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह पूछे जाने पर क्या उद्योग कर दर में और कटौती की अपेक्षा कर रहा है, उन्होंने इससे इनकार किया। किर्लोस्कर ने कहा, ''मुझे लगता है कि मौजूदा दर प्रतिस्पर्धी है। मुझे पता है कि जो लोग थाईलैंड, इंडोनेशिया या भारत में निवेश करने पर गौर कर रहे हैं, उनके लिये भारत रूचिकर बन गया है। मुझे लगता है कि अगले दो साल में आपको परिणाम देखने को मिलेगा।'' उल्लेखनीय है कि सरकार ने सितंबर में कंपनियों के लिये प्रभावी कंपनी दर कम कर 22 प्रतिशत कर दिया। इतना ही नहीं जो कंपनियां 22 प्रतिशत आयकर श्रेणी का विकल्प चुनती हैं.उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर देने की जरूरत नहीं है। एक अक्टूबर के बाद गठित विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिये कर की दर बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत होगी। जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि में नरमी के बारे में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में नरमी कई कारकों का नतीजा है। किर्लोस्कर ने कहा, ''पिछले 5-6 साल में यह अच्छा रहा। नरमी चक्रीय के साथ-साथ संरचनात्मक दोनों है। मामला इतना जटिल है कि इसे सरलता से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि पटरी पर लौटने के लिये हमें स्वयं से पुनर्गठन करना होगा।'' देश की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रही जो छह साल का न्यूनतम स्तर है। किर्लोस्कर सिस्टम लि. के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष किर्लोस्कर ने कहा कि उद्योग मंडलों की वित्त मंत्री के साथ बैठक अच्छी रही। उन्होंने कहा, ''मुख्य बिंदु बजट घाटे पर फिर से गौर, राजकोषीय नीति का थोड़ा विस्तार तथा बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त खच...रहा।'' उद्योग मंडल ने कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भुगतान में विलम्ब के मामले का जिक्र किया।

केन्द्र ने नयी राष्ट्रीय वस्त्र नीति के लिए सुझाव मांगे

नयी दिल्ली। एजेंसी

कपड़ा मंत्रालय ने अगले 10 वर्षों के लिए नयी राष्ट्रीय कपड़ा नीति तैयार करने के बारे में इस उद्योग के साथ हित रखने वाले पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इस नीति का उद्येश्य भारत को कपड़ा क्षेत्र में एक पूरी तरह से एकीकृत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाना है। यह नीति के तहत देश के कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार की जाएगी। पिछले महीने, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा था कि केंद्र सरकार, राज्यों के परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय कपड़ा नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। नई नीति का निर्माण पिछले कुछ समय से विचाराधीन है। 2016 में, कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि नई नीति में अतिरिक्त 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन की परिकल्पना की जायेगी। राष्ट्रीय कपड़ा नीति-2000 के बाद से इस उद्योग ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कई बदलाव देखे हैं। घरेलू कपड़ा उद्योग ने पिछले दशक में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन किया है और कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

रूस के सुदूर पूर्व में तेल गैस क्षेत्र में निवेश के लिये बात कर रहा है भारत: प्रधान

मुंबई। एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट से वहां सुदूर पूर्व क्षेत्र में निवेश को लेकर बातचीत कर रहा है। भारत पहले ही रूस में अच्छी-खासी राशि निवेश कर चुका है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वहां सखालिन-1, तास-यूरियाख और वैंकोर की परियोजनाओं के साथ साथ साइबेरिया में काम कर रही कंपनी इम्पीरियल एनर्जी में करीब 10 अरब डॉलर निवेश कर चुकी हैं। प्रधान ने भारत आर्थिक सम्मेलन 2019 में कहा, ''रूस में हम सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट में उनके सुदूरपूर्व संकुल में निवेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं। भू-राजनीतिक स्थिति में बदलाव, रूस का पूर्वी क्षेत्र बेहतर क्षेत्र के रूप में उभरा है और हम उस पर ध्यान दे रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादक तेल फील्डों में निवेश में रूचि है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के हित में है। देश की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों के बारे में प्रधान ने कहा, ''मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण अनिश्चितता बनी है। इससे ऊर्जा की कीमत पर असर पड़ रहा है। भारत जैसे कीमत संवेदनशील देश के लिये जहां गरीब और निम्न मध्यम वर्ग बड़ी संख्या में रहते हैं...कीमत में उतार-चढ़ाव एक चुनौती है।'' उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरत का 70 से 80 प्रतिशत अभी आयात के जरिये पूरा होता है। सरकार स्वच्छ गैस और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कई कदम उठा रही है। प्रधान ने कहा कि इन कदमों से हमें आयात पर निर्भरता में कमी लाने में मदद मिलेगी।

भारतीय कंपनियां डिजिटाइजेशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं: स्टडी

बेंगलुरु। एजेंसी

भारत डिजिटल ट्रांसफर्मेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम इसके लिए कितने तैयार हैं इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें चेतावनी दी गई है। फोर्सपॉइंट की स्टडी में कहा गया है कि डिजिटल ट्रांसफर्मेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती साइबर अटैक है।

तेजी से हो रहा है डिजिटलाइजेशन

स्टडी में पाया गया कि लगभग 95 फीसदी कंपनियां डिजिटल ट्रांसफर्मेशन की नाव पर सवार हो चुकी हैं, जबकि 61 फीसदी कंपनियों का कहना है कि साइबर अटैक के कारण चुनौती बढ़ती जा रही है। जिन कंपनियों में डिजिटल ट्रांसफर्मेशन हो चुका है उनमें से करीब 46 फीसदी कंपनियों पर साइबर अटैक हुआ है।

क्लाउड कम्प्यूटिंग को लेकर जबर्दस्त रुझान

इस स्टडी में पाया गया कि भारत में तकरीबन 76 फीसदी बिजनस क्लाउड कम्प्यूटिंग को अपना चुकी हैं, लेकिन इन कंपनियों पर खतरा भी काफी बढ़ गया है। इनमें से करीब 47 फीसदी कंपनियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में सिक्योरिटी ब्रीच की समस्या को झेला है।

स्टडी में शामिल हुईं 100 कंपनियां

इस स्टडी में भारत की 100 कंपनियां शामिल हुई थीं। इनमें से 62 फीसदी कंपनियां लार्ज एंटरप्राइजेज हैं जिनका ग्लोबल ऐनुअल टर्नओवर 250 मिलियन डॉलर (करीब 1800 करोड़ रुपये) है। ज्यादातर कंपनियां आईटी और बीपीओ (37 फीसदी) थीं। ँइए सेक्टर की 27 फीसदी कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 19 फीसदी कंपनियां स्टडी में शामल हुई थी।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों को कर्ज भुगतान के लिये स्थिति सामान्य होने का इंतजार

कोलकाता। एजेंसी

सूक्ष्म ऋण संस्थानों को नागरिकता कानून में संशोधन बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन के कारण खास कर असम में ग्राहकों से कर्ज वसूली में इस समय देरी हो रही है। ऐसे संस्थान अपने ग्राहकों, राज्य सरकार तथा नियामकीय निकायों के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति से निपटने में लगे हैं और इस सप्ताह के आखीर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उद्योग संगठन और स्व नियामक संगठन एमएफआईएन के चेयरपर्सन मनोज नाम्बियार ने पीटीआई भाषा से कहा, ''कर्फ्यू और कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति के कारण हम ग्राहकों के साथ बैठक, लोगों से सम्पर्क, ग्राहक समूहों का गठन और नये कर्ज वितरण की तैयारी जैसे सामान्य कार्य नहीं कर पा रहे।'' प्रदेश में पिछले सप्ताह सोमवार से कामकाज प्रभावित है। ऑल असम स्टुडेन्ट्स यूनियन (आसु) नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ तीन दिन का सत्याग्रह आयोजित किया है। कई सूक्ष्म वित्त संस्थानों से इस दौरान सामान्य गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है।सातिन क्रेडिट केयर नेटवर्क के मुख्य परिचालन अधिकारी देव वर्मा ने कहा, ''असम में इंटरनेट सेवाएं ठप होने से भी सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। '' उनके अनुसार सातिन ने असम में करीब 480 करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है और प्रभाव चार-पांच जिलों तक सीमित है। विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज (वीएफएस) के प्रबंध निदेशक कुलदीप मैती ने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये असम संभावना वाला बाजार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण भुगतान की दर लगभग 100 प्रतिशत घटकर 70 से 80 प्रतिशत पर आ गयी है। उ उद्योग सूत्रों के अनुसार करीब 20 सूक्ष्म वित्त संस्थान असम में काम कर रहे हैं और सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार 27 लाख है।

वैज्ञानिक लेखों का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक है भारत : रिपोर्ट

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विषय पर लिखे गए लेखों को प्रकाशित करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा तैयार डेटा के मुताबिक चीन इस मामले में नंबर एक पर है जो दुनिया भर में छपने वाले वैज्ञानिक लेखों में 20.67 प्रतिशत योगदान देता है। मंगलवार को जारी किए गए इन आंकड़ों में बताया गया कि 2008 में, भारत ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विषय पर 48,998 लेख प्रकाशित किए। यह संख्या 2018 में बढ़ कर 1,35,788 लेखों पर पहुंच गई और अब भारत दुनिया भर में इस विषय पर प्रकाशित होने वाले लेखों में 5.31 प्रतिशत का योगदान देता है। चीन में, 2008 में 2,49,049 वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए गए जो 2018 में बढ़ कर 5,28,263 हो गए। वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका (4,22,808) है। शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाने वाले अन्य देशों में जर्मनी (1,04,396), जापान (98,793), ब्रिटेन (97,681), रूस (81,579), इटली (71,240), दक्षिण कोरिया (66,376) और फ्रांस (66,352) है।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए

नयी दिल्ली। एजेंसी

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (इक्विटास एसएफबी) ने 1,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए हैं। एक बयान में दस्तावेजों के मसौदे के हवाले से कहा गया है कि आईपीओ के तहत 550 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इक्विटास होल्डिंग्स लि. (ईएचएल) आठ करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएगी। आईपीओ के तहत 100 करोड़ रुपये के शेयर ईएचएल के पात्र शेयरधारकों के लिए रखे जाएंगे और कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिए पांच करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित रहेंगे। कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध कराया जाएगा।

जन्मकल्याणक (21 दिसंबर) पर विशेष

पंच मुख्य व्रत के प्रवर्तक भगवान पार्श्वनाथ

जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के करीब 1000 वर्षों के बाद 872 ईसा पूर्व में पौष कृष्ण दशमी को विशाखा नक्षत्र में काशी में इक्ष्वाकु वंश मे हुआ था। इनकी माता का नाम वामदेवी तथा पिता का नाम अश्वसेन था। माता जी ने अपने गर्भकाल में स्वप्न में एक बार फणधारी सर्प देखा था, इस कारण बालक का नाम पार्श्व रखा।

महावीर स्वामी के जन्म के करीब 250 वर्ष पूर्व श्री पार्श्वनाथ का आविर्भाव एक युगान्तकारी घटना है। जैन आगम ग्रन्थों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नौ जन्मों का स्पष्ट उल्लेख है। पहले जन्म में मरुभूमि नामक ब्राह्मण, दूसरे मे वज्रघोष नामक हाथी, तीसरे में स्वर्ग के देवता, चौथे में रश्मिवेग नामक राजा, पांचवें में देव, छठे में वज्रनाभि नामक चक्रवर्ती सम्राट, सातवें में देवता, आठवें में आनन्द नामक राजा और नौवें जन्म में इंद्र बनने के बाद दसवें जन्म में पूर्व जन्मों के संचित पुण्य फल के उपरांत इन्हें तीर्थंकर बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।

श्री पार्श्वनाथ का वर्ण नीला, जबकि चिह्न सर्प है। इनके यक्ष का नाम पार्श्व व यक्षिणी को पद्मावती के नाम से जाना जाता है। श्री पार्श्व ने पौष माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को वाराणसी में जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की और उसके दो दिन बाद पायस का प्रथम पारणा किया। मात्र 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक मोहमाया का त्याग कर संन्यासी हो गए और फिर 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। करीब 100 वर्ष की अवस्था में सम्मेद शिखर के ऊंचे शिखर खंड पर आप 772 ईसा पूर्व में श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए, जहां पूर्व काल में कुल 19 तीर्थंकरों को निर्वाण लाभ की प्राप्ति हुई थी। इनके निर्वाण तीर्थ स्मारक को यहां 'टोंक' कहा जाता है।

भगवान पार्श्वनाथ के गणधरों की संख्या 10 थी। इनमें आर्यदत्त स्वामी प्रथम गणधर हुए। श्री पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म के पंच मुख्य व्रत की शिक्षा दी, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य आते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि उनके समय में अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का समावेश एक ही व्रत में होता था। श्री पार्श्वनाथ ने ही चतुर्विध संघ की स्थापना की, जिनमें मुनि, आर्यिका, श्रावक व श्राविका होते हैं। आज भी जैन समाज में यही परम्परा कायम है। उनके चातुर्याम धर्म का उल्लेख बौद्ध साहित्य 'त्रिपिटक' में है। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म को जन-जन के बीच लोकप्रिय बनाकर ऐसा महती कार्य कर गए, जिसकी आभा आज भी जीवंत है।

डॉ. राकेश कुमार सिन्हा 'रवि'

करुणा है संन्यास का प्रमाण

सही मायनों में संन्यास का अर्थ है हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होना। इसके लिए माया-मोह छोड़ना होगा। जब हृदय में करुणा होगी, तभी महावीर की अहिंसा का अर्थ समझ आएगा। बुद्ध की करुणा का अर्थ समझोगे और तब संन्यास की सही दिशा मिल जाएगी।

अध्यात्म

ओशो

संसार के प्रति बहुत माया-मोह हो तो दया का भाव बनेगा ही कैसे? जितना संसार के प्रति माया-मोह होता है, उतना ही चित्त कठोर, हिंसक हो जाता है। जितना संसार की चीजों में लगाव होता है, उतना ही तुम्हारी देने की क्षमता कम हो जाती है, दया कम हो जाती है- दया यानी देने की क्षमता।

तुम जिस दिन सब माया-मोह छोड़ दोगे, उस दिन तुम पाओगे करुणा ही करुणा बची। शुद्ध करुणा बची। वही ऊर्जा जो माया-मोह बनी थी, करुणा बनती है। इसी करुणा के कारण तो बुद्ध बोले। नहीं तो बोलते कैसे? जब माया-मोह ही समाप्त हो गया- तो अब फिर समझाना क्या है? बोलना क्या है? अपनी आंख बंद कर ली होती, चुपचाप अपने में डूबकर समाप्त हो गए होते। नहीं हो सके समाप्त। कोई कभी नहीं हो सका अपने में समाप्त। जब दुख में थे तो चाहे जंगल भाग गए, लेकिन जब सुख मिला तो वापस बस्ती लौट आए। बांटना था! जंगल में किसको बांटते?

इस बात को खयाल में लेना। महावीर चले गए जंगल, जब दुखी थे। बुद्ध भी गए जंगल, जब दुखी थे। जब दुखी थे तो चले जाना एक अर्थ में उचित ही था, क्योंकि यहां रहते तो लोगों को दुख ही देते और क्या होता? दुख हो तो दुख ही हम देते हैं। भाग गए, हट गए यहां से, बीमार आदमी जंगल चला जाए, ताकि कम से कम औरों को तो बीमारी न फैलाए। जब रोग कट जाए, स्वास्थ्य पैदा हो, तब लौट आना, क्योंकि जैसे रोग के कीटाणु होते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य के भी कीटाणु होते हैं। तो परमज्ञानी पुरुष पहले तो भागे जंगल की तरफ; और जब पा लिया, जब हीरा हाथ लगा, तब लौट आए। तब लौटना ही पड़ा, अब यह हीरा बांटना भी तो पड़ेगा।

इस हीरे के मिलते ही एक बड़ा उत्तरदायित्व भी साथ में मिलता है कि अब इसे दो; यह सब को मिल सकता है, अब उनको खबर करो; जगाओ सोये हुओं को। बुद्ध बयालीस साल जिंदा रहे ज्ञान के बाद, बयालीस साल अथक पुकारते रहे-सुबह-सांझ, गांव-गांव चिल्लाते फिरे। चालीस वर्ष महावीर भी ऐसे ही भटकते रहे, पुकारते रहे, चोट करते रहे, किसी भांति कोई जाग जाए।

> पतंजलि ने कहा न- 'रसो वै सः', वह सत्य तो रसमय है, वह परमात्मा तो रस भरा है। संन्यासी रस से थोड़े ही विरुद्ध है! रस संसार में व्यर्थ न बहे, रस दया बनकर बहे, सेवा बनकर बहे; रस तुम्हें याचक न बनाए, दानी बनाए; रस तुम लुटाओ, रस तुम दो।

संन्यासी, जगत के भोग के लिए तो जगत को छोड़ देता है, पर सेवा के लिए नहीं। सेवा के लिए तो वह जगत का हो जाता है, पहली दफा जगत का हो जाता है, और सदा के लिए हो जाता है। भोग छोड़ने के कारण और भी ज्यादा जगत का हो जाता है, क्योंकि जब तक तुम जगत के भोग में उत्सुक हो, तब तक तुम भिखारी हो; तुम मांग रहे हो जगत से, दोगे क्या खाक! जिस दिन तुमने भोग की आकांक्षा छोड़ दी, तुम मालिक बने, तुम सम्राट बने। अब तुम दे सकते हो। भोग के कारण हम सेवा चाहते हैं। भोग छोड़ने पर सेवा देने का प्रारंभ होता है।

जैसे-जैसे संन्यासी वृद्ध होने लगता है, वैसे-वैसे और सुंदर होने लगता है, क्योंकि संन्यास का कोई वार्द्धक्य होता ही नहीं। इसलिए तो हमने बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां बनाई हैं, वह उनके युवावस्था की बनाई हैं। इस बात की खबर देने के लिए कि संन्यासी चिर-युवा है। हमने अपूर्व सौंदर्य से भरी मूर्तियां बनाई हैं महावीर और बुद्ध की। उनके पास कुछ भी नहीं है, न कोई साज है, न शृंगार है... बुद्ध और महावीर के पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध के पास तो एक चीवर है, जिसको ओढ़ा हुआ है। महावीर के पास तो वह भी नहीं। ऐसा सौंदर्य जिसको किसी सजावट की कोई जरूरत नहीं।

तुम्हारे तथाकथित संन्यासी रूखे-सूखे लोग हैं। उन्होंने माया-मोह छोड़ी, उसी दिन से वे डर गए हैं। उन्होंने अपने को सुखा लिया भय के कारण। वे रसहीन हो गए हैं। पतंजलि ने कहा न- 'रसो वै सः', वह सत्य तो रसमय है, वह परमात्मा तो रस भरा है। संन्यासी रस से थोड़े ही विरुद्ध है! रस संसार में व्यर्थ न बहे, रस दया बनकर बहे, करुणा बनकर बहे, सेवा बनकर बहे; रस तुम्हें भिखारी न बनाए, सम्राट बनाए; याचक न बनाए, दानी बनाए; रस तुम लुटाओ, रस तुम दो।

संसार छोड़े, वह तो ठीक, लेकिन करुणा छोड़ चुके! तो फिर तुम बुद्ध की करुणा न समझोगे, महावीर की अहिंसा न समझोगे और क्राइस्ट की सेवा न समझोगे। इसे कसौटी मानकर चलना। करुणा बननी ही चाहिए। तो ही समझना कि संन्यास ठीक दिशा में यात्रा कर रहा है।

(सौजन्यः ओशोधारा नानक धाम, मुरथल)

आस्था स्थली: नौलखा जानकी मंदिर, जनकपुर, नेपाल

यहां आज भी होता है राम-जानकी विवाह

जनकपुर का नौलखा जानकी मंदिर भारत और नेपाल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान राम एवं मां सीता को समर्पित है। यह ऐतिहासिक मंदिर हिन्दू-राजपूत वास्तुकला शैली का सुंदर नमूना है। मंदिर नेपाल के जनकपुर प्रान्त के धनुषा जिला में स्थित है। इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 4,860 वर्ग फीट में फैला है।

मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी की शुद्ध सोने की मूर्तियां हैं। किंवदंती के अनुसार, सीताजी की यह सोने की मूर्ति इसी स्थान पर एक संत सूरदास जी को खुदाई कराने पर 1657 में प्राप्त हुई थी। इसी खुदाई वाली जगह पर नौलखा जानकी मंदिर बना है। मंदिर परिसर के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे में 115 सरोवर एवं कुंड हैं, जिसमें गंगासागर कुंड सबसे पवित्र एवं प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार, इस कुंड को महाराजा जनक ने गंगाजल से भरवाया था। यह कुंड मंदिर परिसर में है। कथाओं के अनुसार, इसी गंगासागर कुंड के जल से सीता जी शिव जी के उस पिनाकी धनुष का अभिषेक करती थीं, जिसके भंग होने के बाद सीता जी और भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर में दर्जनों मंदिर हैं, इनमें सबसे भव्य यह नौलखा जानकी मंदिर ही है। इसका निर्माण टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से करवाया था। मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने के एक वर्ष के अंदर ही वृषभानु कुमारी को पुत्र प्राप्त हुआ। नौलखा जानकी मंदिर के निर्माण काल में ही वृषभानु कुमारी का निधन हो जाने के बाद उनकी बहन नरेंद्र कुमारी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। यहां का मुख्य मंदिर सफेद संगमरमर का है।

प्रमुख मंदिर के पीछे एवं जानकी मंदिर के उत्तर की ओर 'अखंड कीर्तन भवन' है, जिसमें 1961 से सीताराम नाम का कीर्तन 24 घंटे अखंड चलता रहता है। परिसर के भीतर ही राम जानकी विवाह मंडप है। मंडप के खंभों और दूसरी जगहों को मिलाकर कुल 108 प्रतिमाएं हैं। इस मंडप में अगहन माह की पंचमी, जिसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है, को पूरे रीति-रिवाज से प्रतिवर्ष राम-जानकी का विवाह किया जाता है।

जनकपुर में कई अन्य मंदिर और तालाब हैं। प्रत्येक तालाब के साथ अलग-अलग कहानियां हैं। विवाह मंडप के चारों ओर चार छोटे-छोटे 'कोहबर' (वर-कन्या का मिलन गृह) हैं। इनमें सीता-राम, माण्डवी-भरत, उर्मिला-लक्ष्मण एवं श्रुतिकीर्ति-शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं।

कैसे पहुंचें: जनकपुर धाम नेपाल-भारत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। यहां जाने के लिए सबसे सुगम सड़क मार्ग ही है। बिहार के सीतामढ़ी से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। सीतामढ़ी से जनकपुर की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है। बीच में भिट्ठामोड़ एक जगह है, जहां से यात्री नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। भिट्ठामोड़ नेपाल में हैं और वहां से जनकपुर मात्र 15 किलोमीटर दूर है। नजदीकी हवाई अड्डा नेपाल का जनकपुर एयरपोर्ट है। रेलवे से आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन बिहार का सीतामढ़ी है।

बजरंगबली सिंह

अब इलेक्ट्रिक कार लेने में नहीं होगी हिचक!

10 मिनट की चार्जिंग पर कार चलेगी 480km

नई दिल्ली। एजेंसी

इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड भारत में तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी लोग इन्हें खरीदने में हिचक रहे हैं। इसके पीछे की कई वजह हैं, जैसे कि लोगों के पास अभी अलग-अलग कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, गाड़ियों की बैटरी की फास्ट चार्जिंग का सेटअप इतना बेहतर नहीं है, इनकी कीमत काफी ज्यादा है और ये लंबी दूरी तय करने में भी इतनी सक्षम नहीं है...

पुरानी बातों को करेगी गलत साबित

एक खबर के मुताबिक, अब लोगों की इन्हीं परेशानियों का जवाब सामने आ गया है, क्योंकि अमेरिका की झहह ऊ्ली ळहग्नैग्रू के इंजिनियर्स ने एक ऐसी बैटरी बनाई है, जो कि सिर्फ 10 मिनट चार्ज होने पर किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 320 से 480 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में मदद करेगी। बता दें कि किसी इलेक्ट्रिक कार को अगर सुपरफास्ट 'सुपरचार्जर' स्टेशन पर भी चार्ज किया जाए, तो भी उसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 50 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन ये नई बैटरी लोगों को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है और पुरानी सभी बातों को गलत साबित करेगी।

कैसे करती है काम

झहह ऊ्ली में इलेक्ट्रोकेमिकल इंजन सेंटर के डायरेक्टर और बैटरी पर काम करने वाले चाओ यांग वांग का कहना है कि 10-मिनट चार्जिंग का ये ट्रेंड ही फ्यूचर है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि इसकी मदद से रेंज की समस्या का समाधान निकल सकता है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो बैटरी डिजाइन की है, उसमें asymmetric temperature modulation है, जिसमें चार्जिंग डिवाइस को 10 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किया जाता है और इसके बाद उसे तुरंत एम्बियंट (परिवेश) तापमान पर ठंडा किया जाता है। इसकी मदद से लीथियम प्लेटिंग को नुकसान पहुंचे बिना, बैटरी तेजी से चार्ज हो पाती है।

सीधे किसानों से फल-सब्जी खरीदेगी ऐमजॉन, आएंगे उनके 'अच्छे दिन'?

नई दिल्ली। एजेंसी

एक तरफ फूड इन्फ्लेशन नवंबर महीने में पिछले 71 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। प्याज 160 के पार तो आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है। दूसरी तरफ देश के किसान अभाव और कर्ज के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। लेकिन अब इस समस्या का जल्द होने जा रहा है। ऐमजॉन पुणे के किसानों के साथ मिलकर एक पायलट प्रॉजेक्ट पर काम कर रही है।

कोल्ड स्टोरेज का चेन तैयार करेगी ऐमजॉन

ऐमजॉन वहां के किसानों के साथ मिलकर डायरेक्ट बिजनस करना चाहती है। इसके लिए वह वह कोल्ड स्टोरेज का चेन तैयार कर रही है। वह किसानों से सीधा सामान खरीदेगी और उस संरक्षण कोल्ड स्टोरेज में किया जाएगा। बाद में इन सामानों को ऐमजॉन फ्रेश और ऐमजॉन पैन्ट्री के प्लैटफॉर्म पर बेच दिया जाएगा। इससे किसानों को भी सही कीमत मिलेगी और उन्हें तुरंत अपनी फसल का पैसा मिल जाएगा।

सीधे किसानों से होगी खरीद

अगर यह प्रॉजेक्ट सफल होता है तो ऐमजॉन बहुत तेजी से इस बिजनस का विस्तार करना चाहेगी।फिलहाल वह मंडियों से फल और सब्जियां अग्रीगेटर से खरीदती है और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर उसकी बिक्री की जाती है। सवालों का ईमेल जवाब में उसके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम इस प्रॉजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकारी बॉडी से भी संपर्क में हैं।

580 अरब डॉलर का है सालाना व्यापार

भारत में फूड और ग्रॉसरी का सालाना कारोबार करीब 580 अरब डॉलर का है। इसमें ऑर्गनाइज्ड सेक्टर का योगदान मात्र 25 अरब डॉलर का है। इसलिए तमाम ई-कॉमर्स कंपनियां यहां अपने लिए मौके तलाश रही हैं। ऐक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक अगले पांच सालों यानी 2024 तक यह बाजार करीब 69 अरब डॉलर का हो जाएगा। वॉलमार्ट पहले ही बहुत तेजी से इस बाजार में अपनी पहुंच बना रहा है।

EPFO जांच-पड़ताल प्रक्रिया को बनाएगा सरल

शुरू करेगा ई-निरीक्षण प्रणाली

बेंगलुरु। एजेंसी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ई-निरीक्षण प्रणाली शुरू करेगा। इसका उद्देश्य जांच-पड़ताल की प्रक्रिया को सरल बनाना और बिना उचित जरूरत के आमने-सामने पूछताछ की प्रक्रिया को कम करना है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनिल बर्थवाल ने यह जानकारी दी। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक विज्ञप्ति के अनुसार बर्थवाल ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि ईपीएफओ ने उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत जांच की अधिकतम अवधि दो साल होगी। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की गड़बड़ी के चलते कुछ प्रतिशत कर्मचारी यूएएन (12 अंकों वाली सार्वभौमिक खाता संख्या) सृजित नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए ईपीएफओ कर्मचारी डेटाबेस के माध्यम से सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। विज्ञप्ति में बर्थवाल के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफओ केवाईसी का पालन करने वाले लाभार्थियों के लिए मामलों का निपटान तीन दिन के अंदर करने की दिशा में काम कर रहा है। इन लाभार्थियों का यूएएन आधार और बैंक खाता से जुड़ा होता है और इनके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की तर्ज पर सलाहकारों की संस्था बनाने का भी प्रस्ताव है। यह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने उद्योग के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि चूककर्ताओं को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने और इन मामलों को आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है।

वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत अर्जित ब्याज को कर मुक्त बनाने की जरूरत, SBI ने सरकार को दिया सुझाव

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्याज दरों में गिरावट के परिदृश्य के बीच सरकार को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) पर अर्जित ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त करने पर विचार करना चाहिए। एसबीआई के एक अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एससीएसएस को पूरी तरह करमुक्त करने की वित्तीय लागत काफी कम बैठेगी। एससीएसएस के तहत कोई वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक जमा कर सकता है और इसपर मौजूदा ब्याज दर 8.6 प्रतिशत है। इस योजना की अवधि पांच साल की है। इसे तीन और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, एससीएसएस के ब्याज पर पूर्ण कर लगता है, जो इस योजना की सबसे बड़ी अड़चन है। इस योजना में पांच साल के लिए एक लाख रुपए की जमा पर 51,000 रुपए ब्याज बनता है। यह ब्याज आयकर के दायरे में आती है। एसबीआई ईकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि उचित यह होगा कि इस योजना में पूरी तरह कर छूट दी जाए। इससे सरकार को सिर्फ 3,092 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। इसका सरकार के राजकोषीय घाटे पर मामूली 0.02 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा।

चीनी उत्पादन 15 दिसंबर तक 35 प्रतिशत गिरकर 45.8 लाख टन पर: इस्मा

नयी दिल्ली। देश का चीनी उत्पादन चालू विपणन सत्र में 15 दिसंबर तक 35 प्रतिशत गिरकर 45.8 लाख टन पर आ गया है। इसकी वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन में तेज गिरावट है। चीनी का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर है। निजी चीनी मिलों के शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने बुधवार को यह बात कही। विपणन वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में चीनी उत्पादन 70.5 लाख टन था। इस्मा के मुताबिक , 15 दिसंबर 2019 तक 406 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही है जबकि 15 दिसंबर 2018 तक 473 मिलें पेराई कर रही थीं। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में मिलों ने 15 दिसंबर तक 21.2 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 18.9 लाख टन था। हालांकि , महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में तेज गिरावट दर्ज की गई है। यहां चीनी मिलें 15 दिसंबर 2019 तक 7.66 लाख टन चीनी का ही उत्पादन कर सकी हैं। इसकी तुलना में 15 दिसंबर 2018 तक 29 लाख टन का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। इसी प्रकार, तीसरे सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में 15 दिसंबर 2019 तक उत्पादन गिरकर 10.6 लाख टन रह गया। एक साल पहले की इसी समय यह 13.9 लाख टन था। इस्मा ने बयान में कहा, 'महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम है। इसकी वजह दोनों राज्यों में मिलों का देर से काम शुरू करना है।'इसके अलावा, गन्ने की पेराई से चीनी निकालने में भी पिछले साल के मुकाबले कमी आने की सूचना है। दरअसल, चीनी मिलें ताजे गन्ने के साथ बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए गन्नों की भी पेराई कर रहे हैं। गुजरात में 1.52 लाख टन, बिहार में 1.35 लाख टन, पंजाब में 75 हजार टन, तमिलनाडु में 73 हजार टन, हरियाणा में 65 हजार टन, मध्य प्रदेश में 35 हजार टन और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में मिलाकर 30 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ है। इस्मा ने चालू विपणन सत्र में कुल चीनी उत्पादन 21.5 प्रतिशत गिरकर 2.6 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है।

16 दिसंबर से 24 घंटे सातों दिन NEFT ट्रांजैक्शन

मुंबई। एजेंसी

अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन NEFT के जरिये करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 दिसंबर से यह सुविधा आपको सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे मिलने लगी है। पहले यह सुविधा 24 घंटे नहीं मिलती थी। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि अब एनईएफटी के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी। NEFT ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक तरीका है, जिसमें आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी ट्रांजैक्शन का निस्तारण सामान्य दिनों में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे के दौरान तथा पहले और तीसरे शनिवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है।

www.eng-expo.co.in
www.eng-expo.in

Why Should You
Participate in Madhya Pradesh ?

- Explore the unexplored opportunities.
- Biggest automobile hub in India.
- Most flourishing food and grain industry.
- Industrial Development on a rapid pace in Plastic Parks, Textile Parks, SEZs, Pharma Zones.
- Both IIMs and IITs are here
- Cleanest city of India third time in a row (IT'S A HATTRICK).
- Fast infrastructure development.
- Centrally connected transport system.
- Good, peaceful and conducive atmosphere for business development.
- Well equipped communication network.
- Proactive initiatives by the state government.

Central India's Largest SME Exhibition

Industrial ENGINEERING EXPO

CONCURRENT EVENTS

3rd International Industry & Technology Expo

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

INDORE 20 21 22 23 DEC 2019

LABHGANGA EXHIBITION CENTRE

SPONSORED BY: Godrej, Bobcat, Reliable Terrestrials, BHAVYA, MB JIGSON, PPPL

CO-SPONSORED BY: PrimePackIndia, SUPREME PEB, WARPP, OSSWAL, JANATICS, Busy

ORGANISED BY: FUTURE COMMUNICATIONS
CONCURRENT EVENT ORGANISED BY: BME
SPONSORED BY: Sanchay Lines
SUPPORTED BY: Pumps India Valves India, IMPA, INDIAN INDUSTRY FORUM
COMPRESSED AIR PARTNER: Gardner Denver
MEDIA PARTNER: पसार टाइम्स, tradeindia, ENGINEERING REVIEW, Tender247, trade4india
DESIGN PARTNER
BEVERAGE PARTNER: COFFEE BAR
TRANSIT PARTNER: Money4Drive
WEB PARTNER: Creato Web

For Participation Call
9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408
futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।